



2026:AHC:18575

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 16047 वर्ष 2025

ओम प्रकाश यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपने प्रधान सचिव के माध्यम से,

ग्रामीण विकास और 4 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: प्रदीप कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. चूंकि पक्षकारों के बीच प्रतिवाद और प्रत्युत्तर का आदान-प्रदान हो चुका है और प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों के अधिवक्ता आगे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उन्हें खंड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 08.09.2024 के आदेश के अनुसार, जब याचिकाकर्ता खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे, तब उन्हें मुख्यालय से संलग्न किया गया था, जो कि रिट-ए संख्या 15684 वर्ष 2024 में चुनौती का विषय था, जिसका निस्तारण दिनांक 09.09.2024 के आदेश को रद्द करते हुए 11.03.2025 को किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 09.01.2025 को एक आरोप पत्र तामील किया गया, जिसमें चार आरोप शामिल थे। याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.03.2025 को आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, जांच अधिकारी ने 06.06.2025 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच सूचना प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। हालांकि, राज्य सरकार ने 27.08.2025 को आदेश पारित कर 06.06.2025 की जांच सूचना को रद्द कर दिया और एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य जांच अधिकारी की नियुक्ति की, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज के संयुक्त विकास आयुक्त को जांच करने और अपनी सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

4. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को एक क्षण के लिए भी मान्य नहीं ठहराया जा सकता। उक्त तर्क को विस्तार से बताते हुए, यह कहा गया है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 का नियम 9 जांच सूचना पर कार्रवाई का प्रावधान करता है, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कारण दर्ज करने के संबंध में प्रकरण को उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को शासकीय सेवक को सूचित करते हुए पुनः जांच के लिए भेजने की शक्ति प्राप्त है, हालांकि याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचित नहीं किया गया है, जो उत्तर प्रदेश नियम 9(1) के अनुसार एक अनिवार्य शर्त है। शासकीय कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999। आगे यह निवेदन किया गया है कि नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रदत्त शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि कुछ शर्तों के अधीन है, विशेष रूप से तब जब जांच किसी अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई हो और आरोप पत्र में लगाए गए आरोप निश्चित आरोपों की श्रेणी में न आते हों, या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र को अनुमोदित न किया गया हो, या प्राधिकारी को आरोप पत्र तामील न किया गया हो, या शासकीय कर्मचारी को अपने बचाव में गवाह पेश करने की अनुमति न दी गई हो, या अनुरोध के बावजूद मौखिक साक्ष्य दर्ज न किया गया हो। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के पक्ष में पूर्व जांच सूचना को अस्वीकार करने का पूरा आधार यह था कि वह इस संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुरूप नहीं था। इस संबंध में समन्वय पीठ के अजई कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 0 सुप्रीम (एलएल) 1418 और अतुल दरबारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णयों का हवाला दिया गया है। (2016) 0 सुप्रीम (एलएल) 2275.

6. श्री पी.के. श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्राप्त निर्देशों और प्रतिपक्षी द्वारा दायर किए गए प्रति-हलफनामे के आधार पर यह तर्क देने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और दिनांक 06.06.2025 की सूचना वाली जांच विधि के अनुसार नहीं थी। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि इस तथ्य के आधार पर कि उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 9(1) के तहत



याचिकाकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई है, आदेश को रद्द कर दिया जाए और प्रकरण को नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया जाए।

7. मैंने बार में दिए गए सभी तर्कों को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता एक शासकीय कर्मचारी है जिसकी सेवा उत्तर प्रदेश शासकीय कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि जांच अधिकारी की नियुक्ति के बाद, आरोप पत्र सौंपे जाने के बाद, जांच अधिकारी द्वारा 06.06.2025 को एक जांच सूचना प्रस्तुत की गई जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाए गए। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इस सूचना को उचित नहीं पाया और दूसरे जांच अधिकारी द्वारा नई जांच कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश शासकीय कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम का नियम 9।

9. नियम 9(1) के प्रभाव और परिणाम पर विचार किया गया और प्रस्तर 22 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई:

“22. नियम 9 जांच सूचना पर कार्रवाई निर्धारित करता है। नियम 9(1) में प्रावधान है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, प्रकरण को पुनः जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को भेज सकता है, जिसकी सूचना आरोपित शासकीय कर्मचारी को दी जाएगी। जांच अधिकारी तब नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित चरण से जांच शुरू करेगा। नियम 9(2) में प्रावधान है कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी आरोप पर जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, तो वह कारणों को दर्ज करते हुए अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज करेगा। नियम 9(3) में प्रावधान है कि यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो आरोपित शासकीय कर्मचारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा और उसे तदनुसार सूचित किया जाएगा। नियम 9(4) में प्रावधान है कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सभी या किसी भी आरोप पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, इस राय का है कि आरोपित शासकीय कर्मचारी पर नियम 3 में निर्दिष्ट कोई दंड लगाया जाना चाहिए, तो वह एक प्रति देगा। जांच सूचना और नियम 9 के उप-नियम (2) के तहत दर्ज किए गए अपने निष्कर्ष की प्रति आरोपित शासकीय कर्मचारी को दी जाएगी और यदि वह चाहे तो उसे एक उचित निर्धारित समय के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच और आरोपित शासकीय कर्मचारी के अभ्यावेदन (यदि कोई हो) से संबंधित सभी प्रासंगिक अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए और इन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नियमों के नियम 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक या अधिक दंड लगाने का तर्कसंगत आदेश पारित करेगा इन नियमों के नियम 3 में उल्लिखित दंडों का उल्लेख करें और इसकी सूचना आरोपित शासकीय कर्मचारी को दें।"

10. इसके अलावा अजय कुमार (पूर्व) प्रकरण में निम्नलिखित अवलोकन किया गया था।

"25. 1999 के नियमों से यह प्रतीत होता है कि यह एक स्व-निहित संहिता है और इसमें अनुशासनात्मक जांच करने और दंड देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जांच सूचना प्रस्तुत किए जाने के बाद, जहां आरोप सिद्ध हो जाते हैं, अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच सूचना की जांच करता है और यदि उसे जांच सूचना में कोई खामी नहीं मिलती है, तो वह नियम 9(4) के अनुसार आगे बढ़ेगा और शासकीय कर्मचारी को कारण बताओ सूचना जारी करेगा जिसमें उससे उक्त सूचना पर प्रतिक्रिया मांगी जाएगी, और उसे प्राप्त होने पर, और परामर्श के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जहां आवश्यक हो, नियम 3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कोई भी दंड लगा सकता है।

26. यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि नियम 7 के उल्लंघन में जाँच की गई है, जहाँ शासकीय कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है या किसी अन्य ठोस कारण से, तो वह जाँच सूचना को स्वीकार न करने के कारणों को दर्ज करने के बाद नियम 9(1) के तहत पुनर्जाँच का आदेश दे सकता है।

27. नियम 9(1) से स्पष्ट है कि जांच सूचना में पाई गई खामी, जिसके आधार पर पुनर्जाँच का आदेश दिया जाता है, वह जांच के संचालन में 1999 के नियमों के नियम 7 के तहत निर्धारित विशिष्ट प्रक्रिया के उल्लंघन से संबंधित होनी चाहिए। यह पहलू नियम 9(1) के अवलोकन से स्पष्ट है, जिसमें यह प्रावधान है कि "जांच अधिकारी इसके बाद नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित चरण से जांच शुरू करेगा"। इसलिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी 1999 के नियमों के नियम 9(1) के तहत पारित अपने आदेश में जांच कार्यवाही में पाई गई खामी के चरण से पुनर्जाँच का निर्देश दे सकता है। असाधारण परिस्थितियों में, जहां जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के संचालन में पक्षपात या कदाचार का गंभीर आरोप हो, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद नियम 9(1) का भी सहारा ले सकता है।

28. जहाँ जाँच की जाती है:-



- i. किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया हो, या
- ii. यदि आरोपपत्र में लगाए गए आरोप "निश्चित आरोप" की श्रेणी में नहीं आते हैं या आरोपपत्र को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, या
- iii. यदि आरोपपत्र में उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है या आरोपपत्र दाखिल करने की तिथि से 15 दिन से कम समय दिया गया है, या उसमें यह उल्लेख नहीं है कि शासकीय कर्मचारी आरोपपत्र में उल्लिखित किसी भी गवाह से जिरह कर सकता है या अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, या
- iv. यदि शासकीय कर्मचारी को आरोप पत्र विधिवत रूप से तामील नहीं कराया गया है, या
- v. शासकीय कर्मचारी को अपने बचाव में गवाह पेश करने की अनुमति नहीं है, न ही उसके बचाव में उनके अनुरोध के बावजूद मौखिक साक्ष्य दर्ज नहीं किया जाता है; या
- vi. वह इस राय का हो सकता है कि शासकीय कर्मचारी को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया है, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी 1999 के नियमों के नियम 9(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

29. शक्ति के प्रयोग और 1999 के नियमों के नियम 9(1) का स्वाभाविक परिणाम यह है कि पुनर्जांच का आदेश दिए जाने पर पिछली जांच सूचना निरस्त हो जाती है। नियम 9(1) के तहत आदेश पारित होने पर पिछली जांच सूचना का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता और जांच के अगले चरण में शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारण जांच कार्यवाही में खामियों से संबंधित होते हैं। ऐसी दोषपूर्ण जांच, जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने नियम 9(1) के तहत आदेश पारित करते समय घोषित किया है, का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता और इसलिए वह कार्रवाई योग्य नहीं रहती और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।“

11. चूंकि याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश शासकीय सेवक (अनुशासन और अपील) नियमों के नियम 9(1) के तहत अनिवार्य रूप से सूचना नहीं दिया गया है, इसलिए चुनौती दिए गए आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।



(क) प्रथम प्रतिपक्षी, सचिव, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 27.10.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है; (ख) प्रकरण को कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण को वापस भेजा जाता है।

13. पूर्व टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

27 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.